

प्रेषक,

मनीषा पवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

विषय- राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार को बेस चिकित्सालय में उच्चीकरण के फलस्वरूप 30 मेडिकल आफिसर्स (एमओओ) आवासों के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-Construction/ NHM /Staff Quarter/2015-16/7523, दिनांक 17.10.2016, पत्र संख्या-Construction/ NHM /Staff Quarter/2015-16/7521, दिनांक 17.10.2016 एवं पत्र संख्या-Construction/ NHM/Staff Quarter/2015-16/3474, दिनांक 10.10.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-857/XXVIII-4-2016-67(5)/2014टीओसीओ, दिनांक 30.09.2016 के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में रू० 57.88 करोड़ की धनराशि एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों द्वारा धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी है।

भारत सरकार द्वारा सप्लीमेंट्री आरओओपीओ वित्तीय वर्ष 2015-16 में टोकन मनी के रूप में रू० 50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) तथा भारत सरकार द्वारा एनओएचओएमओ आरओओपीओ वित्तीय वर्ष 2016-2017 में उक्त योजना हेतु रू० 1543.43 लाख (रुपये पन्द्रह करोड़ तिरालिस लाख तिरालिस हजार मात्र) के सापेक्ष 30 प्रतिशत धनराशि रू० 463.02 लाख (रू० चार करोड़ तिरैसठ लाख दो हजार मात्र) इस प्रकार कुल रू० 513.02 लाख (रुपये पांच करोड़ तेरह लाख दो हजार मात्र) की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3- उक्त के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति की दिनांक 28.10.2016 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय संबंधी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-1570/139-व्यओविओसओ/राओयोओआओ/2016-2017, दिनांक 16.11.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार को बेस चिकित्सालय में उच्चीकरण के फलस्वरूप 30 मेडिकल आफिसर्स (एमओओ) आवासों के निर्माण हेतु (सिविल कार्यों हेतु रू० 937.78 लाख एवं अधिप्राप्ति कार्यों हेतु रू० 339.11 लाख) परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि रू० 1276.89 लाख (रू० बारह करोड़ छियत्तर लाख उनासी हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4- अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में व्यय वित्त समिति की बैठक के संबंध में नियोजन विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 16.11.2016 के क्रम में राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार को बेस चिकित्सालय में उच्चीकरण के फलस्वरूप 30 मेडिकल आफिसर्स (एमओओ) आवासों के निर्माण हेतु औचित्यपूर्ण रू० 1276.89 लाख (रू० बारह करोड़ छियत्तर लाख ब्यासी हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रू० 513.02 लाख (रुपये पांच करोड़ तेरह लाख दो हजार मात्र) की धनराशि को भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत किए जाने की दशा में ही

निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आहरित कर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त सम्बन्धित कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात् कोई भी आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
4. वर्तमान परिदृश्यों में Energy efficient building का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः भवनों को विश्व स्तर के मानकों के अनुसार Energy efficient बनाए जाने तथा इस हेतु building के सम्बन्ध में विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जाय तथा इस सम्बन्ध में Tata Energy research institute (TERI) द्वारा जारी गाईड लाईन/Representative Designs of Energy का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. सौर उर्जा (Solar Energy) के उपयोग का समुचित प्राविधान किया जाय, यथा सोलर गीजर, सोलर कुकर आदि।
6. निर्माण सामग्री यथा ब्रिक्स, सीमेन्ट, स्टील एवं अन्य का Frequency के अनुरूप NADL Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।
7. कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य का Structural Design सक्षम स्तर से चैक कराकर एक प्रति राज्य योजना आयोग को भी उपलब्ध करायेंगे साथ ही रेन फोर्समेन्ट स्टील की मात्रा Bar bending schedule के आधार पर आंकलित किया जाय तथा बचत के सम्बन्ध में प्र०वि० तथा राज्य योजना आयोग को अवगत कराया जायेगा।
8. Electrical Items जैसे switches, wires, MCB, MCCB, AC आदि Plumbing Items जैसे Bath fittings, Geyser, water tank, pipes आदि Toilet Items, wood items आदि की Market Survey कर डी०एस०आर० दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्व में ही कम से कम 3 निर्माता या उनके authorised/ distributor के Quotations प्राप्त कर Brand Name निर्धारित कर लिया जाय। यदि प्रोक्योरमेन्ट मर्चें की लागत रू० 3.00 लाख से अधिक हो तो कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (यथा संशोधित, 2015) के अनुसार कर लिया जाय।
9. आगणन में कार्यदायी संस्था में डी०एस०आर० की दरें ली गयी हैं एवं उसी के अनुरूप मर्चें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मितव्ययता की दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मर्चों का आगणन में समायोजन करेंगे, जो अपरिहार्य मर्चें हैं। मर्चें डी०एस०आर० में हैं, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व उन मर्चों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय।
10. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
11. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
12. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

